International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

तालिबान शासन के अंतर्गत अफगानिस्तान की विदेश नीति: अंतरराष्ट्रीय मान्यता, सुरक्षा चुनौतियाँ एवं अमेरिका के साथ संबंधों का विश्लेषण

Taliban Regime and Afghanistan's Foreign Policy: An Analysis of International Recognition, Security Challenges and Relations with the United States

मनोज भाटी[1], डॉ० अखिलेश कुमार सिंह[2]

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा, सिरोही (राजस्थान)
[2]सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा, सिरोही (राजस्थान)

सार (Abstract)

अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों और निर्वाचित सरकार दोनों के शक्ति पतन के पश्चात् अगस्त 2021 में तालिबान (आतंकवाद समर्थित विचारधारा) की सत्ता में वापसी ने अफगानिस्तान की आंतरिक राजनीति, आंतरिक व क्षेत्रीय सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नई दिशा प्रदान की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान में बीस वर्ष से ज्यादा समय से चल रहे अपने सैन्य अभियान को समाप्त करते हुए वहां से अपनी राष्ट्रीय सेना को वापस बुला लिया। अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान शासन के समक्ष स्थापित सरकार के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना, आर्थिक संकट से निपटना तथा आतंकवाद संबंधी चिंताओं को दूर करना आदि प्रमुख चुनौतियाँ बनकर उभरीं। यद्यपि तालिबान की विदेश नीति वैचारिक प्रतिबद्धताओं और व्यावहारिक आवश्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही है, किन्तु मानवाधिकार, आतंकवाद तथा समावेशी शासन से संबंधित मुद्दे अभी भी इसकी अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति में बाधक बने हुए हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र तालिबान शासन के अंतर्गत अफगानिस्तान की विदेश नीति का विश्लेषण करता है तथा विशेष रूप से अमेरिका के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों, अंतरराष्ट्रीय मान्यता के प्रश्न तथा क्षेत्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन गुणात्मक (Qualitative) तथा वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक (Descriptive-Analytical) शोध पद्धति पर आधारित है।

मुख्य शब्द: तालिबान, अफगानिस्तान, विदेश नीति, अमेरिका-अफगानिस्तान संबंध, अंतरराष्ट्रीय मान्यता, क्षेत्रीय सुरक्षा।

प्रस्तावना

अफगानिस्तान अपनी ऐतिहासिक विरासत, सामरिक भौगोलिक स्थिति तथा क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता होने के कारण लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति और प्रतिस्पर्धा का आधार बिंदु रहा है। दक्षिण एशिया, केंद्रीय एशिया और पश्चिम एशिया के मिलन बिंदु (संगम) पर स्थित यह देश वैश्विक महाशक्तियों की आपसी होड़, क्षेत्रीय सुरक्षा-संरचना तथा भू-राजनीतिक हितों का प्रमुख केंद्र रह चुका है (Barfield, 2010)। विशेष रूप से इक्कीसवीं सदी में 11 सितंबर 2001 के अलकायदा समर्थित आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका द्वारा आरम्भ किए गए "आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध" (War against Terror) ने अफगानिस्तान को वैश्विक राजनीति के मध्य में ला खड़ा किया। वर्ष 2001 में अमेरिकी नेतृत्व तथा सैन्य हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप तालिबानी शासन को सत्ता से बेदखल कर दिया गया तथा एक नई जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया गया। तथापि लगभग दो दशकों तक चले राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक सुधार के प्रयासों के बावजूद अफगानिस्तान में स्थायी शांति एवं राजनीतिक स्थिरता स्थापित नहीं हो सकी (Rubin, 2013)।

फरवरी 2020 में कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के मध्य संपन्न द्विपक्षीय समझौते ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अनुपस्थिति का मार्ग प्रशस्त किया (Council on Foreign Relations, 2020)। दोहा समझौते की शर्तों के अनुरूप अमेरिका एवं नाटो सेनाओं की क्रमवार वापसी आरम्भ हुई, जिसका परिणाम अगस्त 2021 में उनकी पूर्ण स्वदेश वापसी के रूप में सामने आया। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के पश्चात 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर एक बार फिर से नियंत्रण स्थापित कर अंतरिम सरकार का गठन करके सत्ता संचालन की शुरुआत की। सत्ता परिवर्तन की इस प्रक्रिया ने न केवल अफगानिस्तान की आंतरिक राजनीतिक संरचना को प्रभावित किया, बल्कि क्षेत्रीय तथा वैश्विक शक्ति-संतुलन को भी नई दिशा दी (Ghosh, 2022)। तालिबान ने स्वयं को "इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान" के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए एक अंतरिम सरकार का गठन किया, किन्तु उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वैधता एवं राजनयिक मान्यता प्राप्त करने की थी (Faheem & Khan, 2022)।

तालिबान शासन की विदेश नीति मुख्यतः तीन उद्देश्यों पर केंद्रित दिखाई देती है – अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना, आर्थिक सहयोग एवं निवेश सुनिश्चित करना तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना। यद्यपि तालिबान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि अफगान भूमि का उपयोग किसी भी आतंकवादी संगठन द्वारा नहीं होने दिया जाएगा, फिर भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मानवाधिकार, महिला अधिकार, समावेशी शासन तथा आतंकवादी संगठनों के साथ संभावित संबंधों को लेकर अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं (UNAMA, 2022)। इसके विपरीत चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान तथा मध्य एशियाई देशों ने अपेक्षाकृत व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए तालिबान शासन के साथ द्विपक्षीय संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी है (Faheem & Khan, 2022)।

वर्तमान समय में अफगानिस्तान गंभीर वित्तीय, राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अफगानिस्तान विश्व की सबसे बड़ी मानवीय आपात स्थितियों में से एक का सामना कर रहा है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग खाद्य असुरक्षा और वित्तीय संकट से ग्रसित हैं (UNDP, 2022)। दूसरी ओर, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP), अल-कायदा तथा अन्य उग्रवादी संगठनों की गतिविधियाँ क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं (UNICRI, 2022)। इसके अतिरिक्त, तालिबान सरकार को अब तक व्यापक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी है, जिसके कारण विदेशी सहायता, निवेश और वित्तीय संसाधनों तक उसकी

पहुँच सीमित बनी हुई है (Ghosh, 2022)। इन परिस्थितियों में तालिबान शासन के अंतर्गत अफगानिस्तान की विदेश नीति का अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है।

साहित्य समीक्षा

अफगानिस्तान में तालिबान की दोबारा सत्ता में वापसी और उसके बाद परिवर्तित राजनीतिक, सुरक्षा तथा कूटनीतिक परिस्थितियों पर अनेक विद्वतजनों एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अध्ययन किए गए हैं। बार्नेट रुबिन (Rubin, 2002) ने तालिबान आंदोलन की वैचारिक आधार भूमि, उद्भव तथा क्षेत्रीय राजनीति पर उसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया है। इनके अनुसार तालिबान केवल एक वैचारिक एवं राजनैतिक संगठन ही नहीं, बल्कि दक्षिण और मध्य एशिया की सुरक्षा-संरचना को प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इन्होंने अफगानिस्तान में राज्य-निर्माण, राजनीतिक अस्थिरता तथा बाह्य शक्तियों की भूमिका का अध्ययन करते हुए यह स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान की आंतरिक राजनीति का उसकी विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

तालिबान शासन की पुनर्स्थापना के बाद अफगानिस्तान की स्थिति का विश्लेषण करते हुए घोष (Ghosh, 2022) ने मानवाधिकार संकट, आर्थिक बदहाली, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय मान्यता से संबंधित समस्याओं को रेखांकित किया है। उनके अनुसार तालिबान शासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती केवल सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना नहीं, बल्कि घरेलू वैधता और अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त करना है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र अंतर-क्षेत्रीय अपराध एवं न्याय अनुसंधान संस्थान (UNICRI, 2022) द्वारा तैयार प्रतिवेदन में तालिबान शासन के अंतर्गत आतंकवाद, उग्रवाद तथा क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण किया है। इस प्रतिवेदन में विशेष रूप से इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP), अल-कायदा तथा अन्य उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बताया गया है।

दूसरी ओर, फहीम और खान (Faheem & Khan, 2022) ने तालिबान सरकार की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता के प्रश्न का अध्ययन करते हुए यह तर्क दिया कि अधिकांश देशों का दृष्टिकोण वैचारिक के बजाय व्यावहारिक और रणनीतिक हितों से प्रभावित है। उनके अध्ययन में संयुक्त राज्य अमेरिका, जनवादी चीन, रूस तथा अन्य क्षेत्रीय देशों की नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश शोध तालिबान शासन की आंतरिक राजनीति, सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद अथवा अंतरराष्ट्रीय मान्यता पर केंद्रित हैं। तथापि तालिबान शासन के अंतर्गत अफगानिस्तान की विदेश नीति, अमेरिका के साथ उसके संबंधों, अंतरराष्ट्रीय मान्यता तथा क्षेत्रीय व आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के अंतर्संबंधों का समग्र अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित है। प्रस्तुत शोध-पत्र इसी शोध-अंतराल को भरने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. तालिबान शासन के अंतर्गत अफगानिस्तान की विदेश नीति की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करना।
2. तालिबान सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने हेतु अपनाए गए कूटनीतिक प्रयास का अध्ययन करना।
3. अमेरिका और तालिबान शासन के मध्य विकसित हो रहे राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंधों का मूल्यांकन करना।
4. अफगानिस्तान के समक्ष विद्यमान प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों यथा; आतंकवाद और उग्रवाद के प्रभावों का विश्लेषण करना।
5. अफगानिस्तान की विदेश नीति पर क्षेत्रीय शक्तियों – चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान तथा भारत की भूमिका और प्रभाव का अध्ययन करना।
6. तालिबान शासन की विदेश नीति के समक्ष उपस्थित चुनौतियों एवं संभावनाओं का समग्र मूल्यांकन करना।

शोध पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन गुणात्मक और वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। इस अध्ययन में ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक विधियों का उपयोग किया गया है। तालिबान के सत्ता में पुनरुत्थान और अमेरिका-अफगान संबंधों के विकास की पृष्ठभूमि का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है और विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय मान्यता और सुरक्षा चुनौतियों के बीच संबंधों का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। अध्ययन के दौरान उपलब्ध साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण और तुलना की गई है, जिससे विषय वस्तु का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन संभव हो पाता है। यह एक व्याख्यात्मक अध्ययन है, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य किसी परिकल्पना का परीक्षण करना नहीं, बल्कि समकालीन राजनीतिक और कूटनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करना है।
अध्ययन के लिए सामग्री विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी और अंतरराष्ट्रीय निकायों की रिपोर्टों, नीतिगत दस्तावेजों और प्रतिष्ठित समाचार स्रोतों से एकत्रित की गई है। विशेष रूप से, संयुक्त राष्ट्र (UN), अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), संयुक्त राष्ट्र अंतर-क्षेत्रीय अपराध और न्यायिक अनुसंधान संस्थान (UNICRI), भारतीय वैश्विक मामलों की परिषद (ICWA) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, अफगानिस्तान, अमेरिका और क्षेत्रीय शक्तियों से संबंधित समकालीन अकादमिक साहित्य की भी समीक्षा की गई है।

अध्ययन की सीमाएँ (Limitations of the Study)

यह अध्ययन द्वितीयक साहित्य स्रोतों की समीक्षा से प्राप्त ज्ञान एवं सूचनाओं के विश्लेषण पर आधारित है। अफगानिस्तान की समकालीन राजनीति की प्रकृति और विश्वसनीय प्राथमिक आंकड़ों की सीमित उपलब्धता के कारण, न तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण और न ही साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया गया। इसके अलावा, विश्लेषण मुख्य रूप से अगस्त 2021 से 2025 तक की अवधि में तालिबान शासन की विदेश नीति और संबंधित घटनाक्रमों पर केंद्रित है।

तालिबान की सत्ता में वापसी और विदेश नीति के उद्देश्य

अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी इक्कीसवीं सदी की सबसे महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक प्रघटनाओं में से एक थी। लगभग बीस वर्षों तक चले अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप, राष्ट्र-निर्माण परियोजनाओं तथा जनतांत्रिक संस्थाओं के संगठन के प्रयासों के बावजूद तालिबान ने पुनः अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के मध्य संपन्न दोहा समझौते ने इस प्रक्रिया को निर्णायक रूप से प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकी और नाटो सेनाओं की वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ (Council on Foreign Relations, 2020)। 15 अगस्त 2021 को काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही अशरफ गनी सरकार का पतन हो गया और तालिबान ने "इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान" की पुनः स्थापना की (Ghosh, 2022)।
सत्ता में वापसी के पश्चात तालिबान को अनेक आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक ओर उसे युद्धग्रस्त देश में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करनी थी, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास प्राप्त करना भी आवश्यक था। इस संदर्भ में तालिबान की विदेश नीति केवल पारंपरिक कूटनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि शासन की वैधता, आर्थिक पुनर्निर्माण और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से भी जुड़ी हुई थी (Faheem & Khan, 2022)। इसलिए तालिबान शासन की विदेश नीति को उसके अस्तित्व और स्थिरता की कूटनीति के रूप में भी देखा जा सकता है।

तालिबान शासन की विदेश नीति का पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य 'अंतरराष्ट्रीय मान्यता' (International Recognition) प्राप्त करना रहा है। यद्यपि तालिबान ने देश पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया था, फिर भी अधिकांश देशों ने उसकी सरकार को औपचारिक मान्यता प्रदान नहीं की। अंतरराष्ट्रीय मान्यता केवल कूटनीतिक स्वीकृति का प्रश्न नहीं है, बल्कि इससे आर्थिक सहायता, विदेशी निवेश, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनिधित्व तथा वैश्विक वित्तीय संस्थाओं तक पहुँच भी जुड़ी हुई है (Faheem & Khan, 2022)। इसी कारण तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रीय संगठनों तथा प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखने का प्रयास किया। दूसरा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य 'आर्थिक सहयोग और निवेश प्राप्त करना' था। तालिबान के सत्ता में आने के बाद विदेशी सहायता में भारी कमी आई, अफगानिस्तान की विदेशी परिसंपत्तियाँ फ्रीज कर दी गईं तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया (UNDP, 2022)। ऐसी स्थिति में तालिबान ने चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कतर तथा मध्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया। विशेष रूप से चीन के साथ खनिज संसाधनों, अवसंरचना और बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के संदर्भ में सहयोग की संभावनाएँ तालिबान की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण आयाम बन गईं।

तालिबान की विदेश नीति का तीसरा प्रमुख उद्देश्य 'सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना' था। सत्ता प्राप्ति के बाद भी अफगानिस्तान पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सका। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP) जैसे संगठनों ने तालिबान शासन को चुनौती देना जारी रखा और देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी हमले किए (UNICRI, 2022)। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंतित रहा कि अफगानिस्तान पुनः अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों का सुरक्षित आश्रय न बन जाए। इसलिए तालिबान ने विभिन्न देशों को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि उसकी भूमि का उपयोग किसी भी देश के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त तालिबान की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संतुलित संबंध स्थापित करना भी था। चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान ने तालिबान के साथ संवाद और व्यावहारिक सहयोग बनाए रखा, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अधिक सतर्क रुख अपनाया। इस प्रकार तालिबान ने एक ऐसी विदेश नीति विकसित करने का प्रयास किया जो वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ व्यावहारिक आवश्यकताओं को भी संतुलित कर सके (Faheem & Khan, 2022)।

अतः स्पष्ट है कि तालिबान शासन की विदेश नीति मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय वैधता, आर्थिक पुनर्निर्माण, सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन तथा क्षेत्रीय सहयोग के चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित रही है। हालांकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति में मानवाधिकार, महिला अधिकार और समावेशी शासन जैसे मुद्दे अभी भी महत्त्वपूर्ण बाधा बने हुए हैं, जिनका प्रभाव अफगानिस्तान के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

अंतरराष्ट्रीय मान्यता का प्रश्न और अमेरिका–तालिबान संबंध

तालिबान शासन के सामने सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना है। अगस्त 2021 में सत्ता हथियाने के बावजूद तालिबान सरकार को अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अधिकांश देशों द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी सरकार की मान्यता केवल उसकी विधिक स्वीकार्यता का प्रश्न नहीं होती, बल्कि इससे कूटनीतिक प्रतिनिधित्व, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सहभागिता, आर्थिक सहयोग तथा विश्वस्तरीय आर्थिक मंचों तक पहुँच भी जुड़ी होती है (Faheem & Khan, 2022)। इसलिए तालिबान की विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह भरोसा दिलाना रहा है कि वह अफगानिस्तान में स्थिर शासन स्थापित करने में सक्षम है।

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने तालिबान सरकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता देने के मुद्दे पर अत्यंत विचारणीय दृष्टिकोण अपनाया है। इसके पीछे तीन कारण प्रमुख हैं। पहला कारण, मानव के अधिकार; विशेष रूप से महिला अधिकारों से संबंधित अनिश्चितताएं । दूसरा कारण, एक समानता आधारित राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में तालिबान की अस्वीकृति । तीसरा कारण, आतंकी गुटों के साथ उसके अवश्यंभावी सांठ-गांठ को लेकर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की शंकाएँ (Ghosh, 2022)। अमेरिकी सरकार ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि तालिबान की अंतरराष्ट्रीय मान्यता उसके व्यवहार और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के प्रति उसकी कार्यप्रणाली पर निर्भर करेगी।

अमेरिका और तालिबान संबंधों में अस्पष्टता की स्थिति देखने को मिलती रही है। एक ओर दोनों राज्य फरवरी 2020 के दोहा समझौते के माध्यम से प्रत्यक्ष बातचीत कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता में दोबारा आने के बाद तालिबान और अमेरिका के बीच अविश्वास की स्थिति बनी हुई है (Council on Foreign Relations, 2020)। अमेरिका ने अफगानिस्तान की परिसंपत्तियों को फ्रीज कर दिया तथा आर्थिक प्रतिबंधों को बनाए रखा। इससे तालिबान सरकार की आर्थिक मुसीबतें और अधिक बढ़ गईं। तालिबान लगातार इस मनाही को हटाने और अफगान केंद्रीय बैंक की परिसंपत्तियों को स्वतंत्र करने की मांग करता रहा है, जबकि अमेरिका इसे तालिबान शासन के व्यवहार और सुरक्षा संबंधी चिंताओं से जोड़कर देखता है (UNDP, 2022)।

यद्यपि अमेरिका को इस बात की भी आशंका है कि अफगानिस्तान दोबारा विश्व भर में फैले आतंकी गुटों का सुरक्षित निवास न बन जाए। अगस्त 2022 में काबुल में अलकायदा के प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी की अमेरिका द्वारा किए गए ड्रोन हमले में हुई मृत्यु ने इस मुद्दे को और अधिक संवेदनशील बना दिया। इस घटना ने अमेरिका के उस चिंता को बल दिया कि तालिबान अपने संकल्पों के बावजूद आतंकवादी तत्त्वों के विरुद्ध पर्याप्त कार्रवाई करने में अक्षम रहा है (Ghosh, 2022)। दूसरी ओर, तालिबान ने इस ड्रोन हमले को अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप बताया और इस कदम की आलोचना की। इससे स्पष्ट होता है कि सुरक्षा और आतंकवाद का मुद्दा दोनों पक्षों के संबंधों में सबसे विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

इसके बावजूद अमेरिका और तालिबान के बीच पूर्ण गतिरोध की स्थिति नहीं है। इंसानी सहायता, नागरिकों की आवाजाही, आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा कुछ तकनीकी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सीमित बातचीत जारी रही है। इसे "औपचारिक मान्यता के बिना संवाद एवं संपर्क की नीति" (Engagement without Recognition) कहा जा सकता है (Faheem & Khan, 2022)। यह नीति अमेरिका को अफगानिस्तान में अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने का अवसर प्रदान करती है, जबकि तालिबान के लिए यह अंतरराष्ट्रीय अलगाव को कम करने का माध्यम है।

वर्तमान परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि अमेरिका और तालिबान के द्विपक्षीय संबंध मदद और प्रतियोगिता दोनों तत्त्वों से प्रभावित हैं। जहाँ तालिबान अंतरराष्ट्रीय वैधता और आर्थिक सहयोग प्राप्त करना चाहता है, वहीं अमेरिका मानव अधिकार, समानता आधारित शासन और आतंकवाद समाप्ति के संकल्पों को प्राथमिकता देता है। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच सीमित बातचीत तो हो रही है, किंतु पूर्ण कूटनीतिक सामान्यीकरण और औपचारिक मान्यता की संभावना निकट भविष्य में अभी भी सीमित दिखाई देती है।

सुरक्षा चुनौतियाँ और क्षेत्रीय प्रभाव

सुरक्षा, तालिबान शासन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनी हुई है। हालाँकि अगस्त 2021 के बाद से अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर गृह-संघर्ष और बड़ी सैन्य झड़पों में कमी आई है, फिर भी देश आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं से जूझ रहा है। ये चुनौतियाँ न केवल

अफगानिस्तान के घरेलू राजनीतिक माहौल को प्रभावित करती हैं, बल्कि इसकी विदेश नीति और क्षेत्रीय संबंधों पर भी गहरा असर डालती हैं (UNICRI, 2022)।

सत्ता में लौटने के बाद, तालिबान ने वादा किया था कि अफ़गानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद, कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों से पता चलता है कि अलकायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP), तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और अन्य क्षेत्रीय चरमपंथी समूह अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं (Ghosh, 2022)। इनमें से, ISKP तालिबान शासन के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा बनकर उभरा है। इस समूह ने काबुल, कुंदुज, कंधार, नंगरहार और अन्य प्रांतों में कई घातक हमले किए हैं, जिनमें धार्मिक अल्पसंख्यकों, सरकारी संस्थानों और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है (UNICRI, 2022)। इन घटनाओं ने पूरे देश में सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता कायम करने की तालिबान की क्षमता पर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

अफगानिस्तान में अलकायदा की लगातार मौजूदगी भी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अगस्त 2022 में काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा नेता अयमान अलजवाहिरी के मारे जाने से यह साबित हुआ कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तत्त्व अफगानिस्तान के भीतर काम कर रहे हैं (Ghosh, 2022)। इस घटना ने अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों की इन चिंताओं को और पुख्ता कर दिया कि तालिबान ने अभी तक आतंकवादी संगठनों से अपने संबंध पूरी तरह से खत्म नहीं किए हैं। नतीजतन, अफगानिस्तान को व्यापक अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलने की संभावनाएँ अनिश्चित बनी हुई हैं।

तालिबान शासन के सामने एक और बड़ी चुनौती आंतरिक राजनीतिक विरोध है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट (NRF) और कई छोटे प्रतिरोध समूहों ने तालिबान के खिलाफ सीमित सशस्त्र गतिविधियाँ जारी रखी हैं, खासकर पंजशीर और कुछ अन्य क्षेत्रों में (Ghosh, 2022)। हालाँकि ये समूह अभी तालिबान शासन के लिए कोई अस्तित्व का खतरा पैदा नहीं करते हैं, लेकिन इनकी लगातार मौजूदगी यह बताती है कि अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाई है। इसके अलावा, तालिबान के अलग-अलग गुटों—खासकर हक्कानी नेटवर्क, कंधार नेतृत्त्व और दोहा बैठक के बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेद की खबरों ने काफी ध्यान खींचा है (UNICRI, 2022)।

अफगानिस्तान के पड़ोसी देश भी वहाँ की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर काफी चिंतित हैं। पाकिस्तान लंबे समय से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की गतिविधियों पर चिंता जताता रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस्लामाबाद का आरोप है कि TTP के चरमपंथी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर हमले करने के लिए एक बेस के तौर पर कर रहे हैं। यह स्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि 2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद, पाकिस्तान उन शुरुआती देशों में से एक था, जिन्होंने तालिबान शासन के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखे (Faheem & Khan, 2022)।

शिनजियांग इलाके की सुरक्षा और उइगर चरमपंथी संगठनों की संभावित गतिविधियां चीन की मुख्य चिंताएं हैं। बीजिंग उन समूहों को अफगानिस्तान का सुरक्षित ठिकाना बनाने से रोकना चाहता है जो चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। नतीजतन, चीन ने तालिबान के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं और साथ ही निवेश और आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है। इसी तरह, रूस और मध्य एशियाई देशों को भी चिंता है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ और अस्थिरता मध्य एशिया तक फैल सकती है। इसलिए, रूस ने भी तालिबान के साथ बातचीत की रणनीति अपनाई है (Faheem & Khan, 2022)।

भारत के लिए, अफगानिस्तान में हो रहे घटनाक्रम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। भारत की मुख्य चिंता यह है कि लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन भारत-विरोधी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अफगान इलाके का उपयोग कर सकते हैं (Ghosh, 2022)। इसलिए, भारत ने तालिबान सरकार के प्रति सतर्क रुख अपनाया है और साथ ही अफगानिस्तान में बदलती सुरक्षा स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है।

यह साफ है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा चुनौतियां उसके घरेलू राजनीतिक हालात से कहीं आगे तक फैली हुई हैं और इनका क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति पर सीधा असर पड़ता है। आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ, सीमा-पार सुरक्षा खतरे, शरणार्थियों का आना-जाना और राजनीतिक अस्थिरता अफगानिस्तान की विदेश नीति को आकार देते रहे हैं। नतीजतन, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तालिबान के लिए न केवल घरेलू शासन का मामला बन गया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता हासिल करने, राजनयिक संबंध मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी एक जरूरी शर्त बन गया है।

तालिबान शासन की विदेश नीति: एक समग्र जमीनी पड़ताल

अगर अफगानिस्तान की मौजूदा विदेश नीति को देखें तो साफ है कि तालिबान सरकार अपने पुराने विचारों और असल जरूरतों के बीच किसी तरह संतुलन साधने की कोशिश में है। सत्ता में लौटने के बाद सबसे बड़ा सवाल उनके सामने यहीं रहा कि वे बाकी दुनिया के साथ कैसे अपने वैध, स्वीकार्य रिश्ते जोड़ें। खुद को देश का शासक बताने के बावजूद तालिबान को अब तक अंतरराष्ट्रीय मान्यता बहुत सीमित ही स्तर पर मिली है। यही रिक्तता उनकी विदेश नीति को आगे बढ़ने से रोकती है (Faheem & Khan, 2022)।

तालिबान की विदेश नीति में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाल के वर्षों में उनका ध्यान पास-पड़ोस के देशों की तरफ ज्यादा गया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के सतर्क रुख के चलते तालिबान ने चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देशों से सांचे के बाहर रिश्ते गहरे करने की कोशिश की है। खासकर चीन और रूस, अफगानिस्तान में स्थिरता और अपने रणनीतिक हितों को देखते हुए उनसे लगातार बातचीत में रहे हैं। इससे दिखता है कि अफगानिस्तान अब धीरे-धीरे पश्चिमी देशों से दूर हटता हुआ इलाके के बाकी देशों से जुड़ने पर जोर दे रहा है।

वैसे, तालिबान ने कूटनीतिक स्तर पर गतिविधियां तो बढ़ाई हैं, लेकिन मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सर्वसमावेशी शासन जैसे मुद्दे आज भी उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। अमेरिका और यूरोप के नजरिए से देखें तो किसी सरकार की असल पहचान सिर्फ सत्ता संभालना नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय नियमों और जिम्मेदारियों को निभाना भी जरूरी है (Ghosh, 2022)। इसी वजह से ज्यादातर पश्चिमी देशों ने तालिबान से बातचीत जारी तो रखी हैं, लेकिन औपचारिक मान्यता देने से अब भी कतरा रहे हैं।

रही बात अमेरिका-तालिबान रिश्तों की, तो वहां भी मामला काफी उलझा हुआ है। दोनों के बीच सीधी बातचीत हो रही है, मगर आतंकवाद, मानवाधिकार, और आर्थिक पाबंदियों जैसे मसले अकसर तनातनी पैदा कर देते हैं। अमेरिकी रुख फिलहाल "मान्यता के बिना बातचीत" (Engagement without Recognition) वाले फॉर्मूले पर चलता दिखता है (Faheem & Khan, 2022)। दूसरी तरफ तालिबान भी यही चाहता है कि किसी तरह अमेरिकी और बाकी दुनिया से खुद को पूरी तरह अलग-थलग न पड़ने दे, भले यह रिश्ता सीमित ही क्यों न रहे।

कुल मिलाकर, तालिबान की विदेश नीति अभी एक तरह की अस्थायी, बदलती हुई स्थिति में है। यह कितना सफल हो पाएगा, इस पर सब कुछ टिका है कि अब तालिबान सरकार घरेलू स्थिरता, आर्थिक निर्माण, आतंकवाद-रोधी कदम और मानवाधिकारों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय दबावों को एक साथ कैसे संभालती है। अगर उसने इन तमाम चुनौतियों के

ठीक से जवाब ढूंढ लिए, तो शायद आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय मान्यता और कूटनीतिक पकड़ भी मजबूत हो जाए - वर्ना अफगानिस्तान के लिए अलग-थलग रहना और आर्थिक दिक्कतें झेलना आम बात बनी रह सकती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

अगस्त 2021 में जब तालिबान ने दोबारा सत्ता संभाली तो अफगानिस्तान के भीतर सब कुछ बदल गया, लेकिन इसकी गूंज पूरे परिक्षेत्र और दुनिया की राजनीति में भी सुनाई दी। अमेरिकी और नाटो सेना जब चली गईं, तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर पूरी पकड़ बना ली। पर अब भी उनकी सरकार को मान्यता, आर्थिक हालात सुधारना और अंतरराष्ट्रीय दुनिया में जगह पाना आदि ये सब बड़ी मुश्किलें हैं। इस अध्ययन से सामने आया है कि तालिबान की विदेश नीति ज्यादा तर इस कोशिश में लगी रही है कि उसे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिले, आर्थिक सहयोग जुटे, पड़ोसी ताकतों से रिश्ते मजबूत बनें और सुरक्षा की समस्याओं से निपटना भी जरूरी बना रहा।

एक बात और साफ दिखती है - तालिबान ने विदेश नीति में काफी हद तक व्यावहारिक सोच अपनाई है। चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देशों के साथ बातचीत और सहयोग उसी का हिस्सा है। दूसरी ओर, अमेरिका और पश्चिमी देश अब भी मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार, सबको साथ लेकर चलने वाले शासन और आतंकवाद को लेकर सतर्क हैं। यही वजह है कि तालिबान की सरकार अब भी पूरी तरह से दुनिया में मान्यता नहीं पा सकी।

सुरक्षा की चिंता भी अफगानिस्तान की विदेश नीति की दिशा तय करती रही है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP), अल-कायदा और बाकी चरमपंथी संगठनों की हलचल सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के पूरे इलाके के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। ऊपर से पाकिस्तान, चीन, रूस, भारत और मध्य एशिया के देश भी अपनी-अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्र में रहते हैं, जो उनके अफगानिस्तान से रिश्तों पर असर डालती है। यानी सुरक्षा और विदेश नीति आपस में गहराई से जुड़ी हैं।

अगर अमेरिका और तालिबान के रिश्तों की बात करें तो न पूरा गाढ़ा सहयोग है, न ही पूरी टकराहट। दोनों के बीच फिलहाल सीमित बातचीत, मानवीय मदद और रणनीतिक अविश्वास तीनों का मिला-जुला माहौल मौजूद है। अमेरिका की रणनीति है कि वो बिना औपचारिक मान्यता के भी संवाद बनाए रखे (Engagement without Recognition), जबकि तालिबान कोशिश कर रहा है कि उसे किसी तरह वैश्विक स्तर पर वैधता मिल जाए और उसके इसी मक़सद से वो अमेरिका समेत दूसरी ताकतों से बातचीत जारी रखता है (Ghosh, 2022)।

सब मिलाकर, निष्कर्ष यही निकलता है कि तालिबान की विदेश नीति कितनी सफल होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो अपने देश के अंदर स्थिरता ला पाता है, आर्थिक हालात सुधारता है, आतंकवाद की रोकथाम करता है और मानवाधिकार जैसी अंतरराष्ट्रीय उम्मीदों को कैसे संभालता है। अगर तालिबान सरकार समावेशी शासन, महिला शिक्षा और मानवाधिकार के मामले में सही दिशा में बढ़ती है, तो उसे दुनिया में स्वीकृति मिल सकती है। साथ ही आस-पास के देशों और पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को भी अफगानिस्तान से रचनात्मक बातचीत बनाए रखनी चाहिए, ताकि देश फिर से संकट, आतंकवाद और इंसानी त्रासदी का गढ़ न बन जाए।

सुझाव

1. तालिबान सरकार को ऐसी पारदर्शी शासन व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की समान हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व हो।
2. महिलाओं की शिक्षा और मानवाधिकारों के मामले में ऐसे सुधार जरूरी हैं, जो दुनिया भर में तय किए गए मानकों से मेल खाते हों।

3. आतंकवादी संगठनों पर ठोस कार्रवाई करनी होगी, बिना किसी प्रश्रय के तभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भरोसा बन पाएगा।
4. विदेश नीति में क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक रिश्तों को केंद्र में रखना चाहिए।
5. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मानवीय मदद जारी रखते हुए सबसे पहले अफगान जनता के हितों पर ध्यान देना चाहिए।

संदर्भ सूची (References)

1. Barfield, T. (2010). *Afghanistan: A Cultural and Political History*. Princeton University Press.
2. Council on Foreign Relations. (2020). *What to Know About the Afghan Peace Negotiations*. Council on Foreign Relations.
3. Faheem, M., & Khan, M. M. (2022). Recognition of the Taliban Government in Afghanistan and International Community. *Strategic Studies*, *42*(1), 81–96.
4. Ghosh, A. (2022). *One Year after the Taliban Takeover of Afghanistan*. Indian Council of World Affairs (ICWA), New Delhi.
5. International Crisis Group. (2022). *Afghanistan's Security Challenges under Taliban Rule*. International Crisis Group Report.
6. Nojumi, N. (2002). *The Rise of the Taliban in Afghanistan: Mass Mobilization, Civil War, and the Future of the Region*. Palgrave Macmillan.
7. Rashid, A. (2010). *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia* (2nd ed.). Yale University Press.
8. Rubin, B. R. (2002). *The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System* (2nd ed.). Yale University Press.
9. United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). (2022). *Human Rights in Afghanistan: Annual Report 2022*. United Nations.
10. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Afghanistan Socio-Economic Outlook 2022: A Rapid Appraisal*. United Nations Development Programme.
11. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI). (2022). *The Taliban in Afghanistan: Assessing New Threats to the Region and Beyond*. UNICRI.
12. United Nations Security Council. (2022). *Report of the Secretary-General on the Situation in Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security* (A/76/667–S/2022/64). United Nations.
13. United States Institute of Peace (USIP). (2022). *The Taliban's Foreign Policy and International Engagement*. United States Institute of Peace.
14. World Bank. (2022). *Afghanistan Development Update: Coping with Crisis*. World Bank.
15. World Bank. (2023). *Afghanistan Welfare Monitoring Survey*. World Bank.